



भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग  
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय  
केरल, एम.जी.रोड, डाक थैला सं 5607,  
तिरुवनंतपुरम - 695 039  
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)  
KERALA, M.G. ROAD, P.B. No. 5607  
THIRUVANANTHAPURAM - 695 039

P19/II/DRSSA-64/MP/2018-19

26/07/2018

सं/No. ....

दिनांक /Date : .....

To,

**All District/Sub Treasury Officers,**

Sir,

**Sub:** Grant of dearness relief to the Retired Judicial officers/ family pensioners  
of the State of Madhya Pradesh- revised rate 142% effective from 01/01/2018

**Ref:** 1. No. Pension/General/S.S./2536 dated 05/07/2018 under Special  
Seal Authorisation of the Accountant General (A&E), Madhya Pradesh

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the Accountant General (A&E), Madhya Pradesh regarding the grant of dearness relief at a rate of **142% effective from 01/01/2018 on pension/ family pension to Madhya Pradesh State Government Pensioners retired as a Judicial Officers**. The same is being placed in the official website of this office ([www.agker.cag.gov.in](http://www.agker.cag.gov.in)) under the link "*Treasury endorsement of orders for other state pensioners*". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

Accounts Officer

Copy to:-

The Director of Treasuries  
Thiruvananthapuram

Accounts Officer





PM/2/324/2018-19  
25/9/18  
5-7-18

Date :- 06/2018

No. Pension /General/S.S./ 2536

To,

The Principal Accountant General,

(A&E) - Kerala, Tiruvananthapuram

- 695039

Sub.: Regarding grant of Dearness Relief @ 142% w.e.f. 01-01-2018 on Pension/Family Pension to the Madhya Pradesh State Government Pensioners retired as a Judicial Officer.

Sir,

I am enclosing here with copy of The Government of Madhya Pradesh Law and legislative - Department Bhopal Order No. 3(ए)19/2003/21-ब (एक) 2624 Bhopal Dated May 2018 Along with Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure Order No. 1/3/2008-E.II(B) Dated 28<sup>th</sup> March, 2018 regarding the above subject and to state that instruction contained there in may be followed strictly and the entire pension disbursing authorities in the state may be directed suitably to pay relief to the pensioners of Government of Madhya Pradesh of without delay

Enclosed:- As above.

Your faithfully

Accounts Officer / Pension

Date :- 5-7-18

No. Pension/General/S.S./

Endt. Copy for information to :-

- (1) The Chief Secretary - Government of Madhya Pradesh Law and Legislative Department - M.P. Bhopal for information with reference to your letter No. 3(ए)19/2003/21-ब (एक) 2624 Bhopal Dated May 2018.

sd/-  
Accounts Officer / Pension

To  
PIG  
H  
AAH/PM

Hemant



# मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्र.3(ए) 19/2003/21-ब(एक)2624

भोपाल, दिनांक .05.2018

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,  
म.प्र. उच्च न्यायालय,  
जबलपुर (म.प्र.)

001874

विषय:- मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षित दर से पेंशन पर राहत का भुगतान।

केन्द्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008-ई-11(बी), दिनांक 28.03.2018 द्वारा पूर्व पुनरीक्षित (छठवा वेतनमान) प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिनांक 01.01.2018 से 139 से बढ़ाकर 142 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम-9 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर केन्द्रीय कर्मचारियों को प्रदाय महंगाई भत्ता के समान न्यायिक सेवा के कार्यरत सदस्यों को भी महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती रही है। उक्त नियम 2010 के नियम-11(3) के अंतर्गत न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त सदस्यों को सेवारत सदस्यों के समान ही महंगाई भत्ता/ राहत की पुनरीक्षित दरें लागू होंगी।

अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम-11(3) के अंतर्गत मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को दिनांक 01.01.2018 से पेंशन पर राहत 139 प्रतिशत से बढ़ाकर 142 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(1) पुनरीक्षित दरों से महंगाई राहत का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008-ई-11(बी), दिनांक 28.03.2018 में बताई गई रीति से होगा।

(2) इस आदेश के तहत देय महंगाई राहत का भुगतान दिनांक 01.01.2018 से नगद किया जावेगा।

(3) इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाए जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वसूली योग्य होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

DA-30  
7-6-18

Sb Memgob/

